bjpkamaljyoti@gmail.com संवत 2078 युगाब्द 5123 मूल्य : ₹10 अंक – 10, दिसम्बर द्वितीय अंक 2021, कुल पृष्ठ – 32

वर्तमान कमल ज्योति

सुराज की विचार यात्रा

सुशासन अंक

जन-जन का
विश्वास!
यूपी० + योगी = उपयोगी

वर्तमान
कमल ज्योति

संरक्षक
श्री स्वतंत्र देव सिंह
सम्पादक
अरुण कान्त त्रिपाठी
प्रबन्ध सम्पादक
राजकुमार
प्रकाशक
प्रो0 श्याम नन्दन सिंह
पृष्ठ संयोजक
ओम प्रकाश पंडित

कार्यालय

कमल ज्योति, 7–विधानसभा मार्ग
लखनऊ – 1
फोन :– 0522–2200187
फैक्स :– 0522–2612437

Email-
bjpkamaljyoti@gmail.com

पत्रिका में प्रकाशित आलेखों से सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं

मुद्रक

नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र,
राजेन्द्र नगर, लखनऊ–4

अटल श्रद्धांजलि

संपादकीय

सुशासन से जनविश्वास तक

चुनाव सन्निकट है। भाजपा प्रदेश के हर कोने में हर आम और खास के साथ मौजूद है। जन और विश्वास के साथ भाजपा अपनी जनविश्वास यात्राएं लेकर जनता के द्वार पर जा है। यात्राओं में उमड़ती भीड़ और इस भीड़ का भाजपा के प्रति निरंतर घना होता विश्वास एक नई कहानी सुना रहा है। इस दिख रही कहानी का अगर कोई गणितीय शास्त्र है तो उसको उन राजनीतिक पंडितों को गौर से देखना चाहिये जिनको भाजपा सरकार के कार्यों को लेकर निरंतर संदेह के बादल मंडराते रहते हैं लेकिन उनका राजनीतिक पंडितों की बातों को जन का मिल रहा असीम विश्वाय कह रहा है कि.... अब बदल गया है यूपी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास की नीति और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुशासन का ही असर है कि उत्तर प्रदेश का रूप आज पूरी तरह से बदला हुआ है। चुस्त-दुरुस्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और उद्योगों की दिशा में लगातार तरक्की अगर किसी ने की है तो वह उत्तर प्रदेश ही है। अपने कार्यकाल में ही भाजपा ने न केवल कल्याणकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाया, बल्कि उन्हें सभी वर्ग व जाति के लोगों तक बिना भेदभाव पहुंचाया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास' मंत्र के साथ आगे बढ़े और आज प्रदेश में व्यक्तिगत रूप से आम जन को यह संतुष्टि है कि उन्होंने भाजपा को जिस नीतियों को लागू करने और प्रदेश को आगे बढ़ोनके संकल्प के साथ साढे तीन करोड वोट दिये थे उन सभी की आशाओं और आंकाक्षाओं को सरकार ने अपनी नीतियों को इसके अनुरूप क्रियान्वित करके सफल बनाया है। भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है कि, उत्तर प्रदेश 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' से 'ईज आफ लाइफ' की दिशा में बढ़ रहा है।

24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा और सुशासन के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों से देश और दुनिया की धारणा को बदला है। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के समय "यह वही उत्तर प्रदेश रहा है जहां पेशेवर माफिया सत्ता के संरक्षण में अराजकता और भय फैलाते थे। प्रदेश में दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन गई थी और 2012 से 2017 के बीच हर तीसरे दिन औसतन एक बड़ा दंगा होता था लेकिन भाजपा सरकार के पूरे हो रहे वर्षों में राज्य में एक भी दंगा नहीं हुआ।

यह वह प्रदेश रहा है जहां पर पहले लोग मुख्यमंत्री बनते थे तो अपने स्वयं के आवास और बड़ी-बड़ी हवेली बनाने के लिए इनमें प्रतिस्पर्धा लग जाती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने प्रदेश के आम लोगों के लिए 42 लाख आवास बनाए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा और सुशासन मण्डल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। प्रदेश सरकार ने सुरक्षा और सुशासन का जो मण्डल दिया है उसे देश और दुनिया देख रही है और कोरोना प्रबंधन के लिए सरकार के प्रयासों को दुनिया भर में सराहा जा रहा है।

akatri.t@gmail.com

विश्वास विजय का अटल लिये...

साधक राजकुमार

उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान, चुनाव घोषित होने के पूर्व ही जारी हो गया है। भाजपा को टककर देने के लिए विपक्षी, कांग्रेस, बसपा, सपा, अपनी पूरी ताकत लगाये हैं। छोटे दलों से समझौता, जातिया गणित, साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण जारी है, दूसरी तरफ भाजपा अपने विकास कार्यों, मजबूत संगठन, जनसहयोग के सहारे विश्वास विजय का अटल लिये हर द्वार पर दस्तक दे रही है।

भारतीय जनता पार्टी ने जनविश्वास 6 यात्राओं के माध्यम से उत्तरप्रदेश की समस्त 403 विधानसभाओं में मोदी और योगी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को लेकर जन–जन तक पहुँचने का लक्ष्य पूरा कर रही है। 19 दिसंबर से शुरू हुई यह यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग प्रमुख स्थानों से एक साथ शुरू हुई, जिनका शुभारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह, श्री नितिन गडकरी, श्रीमती स्मृतिईरानी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने विशाल जनसभा को सम्बोधित किया।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भाजपा सरकार है तो विकास है, लोगों का सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा है। अन्य दलों की सरकार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि न तो उनकी ये सोच है और न ही ऐसा करने की उनकी मानसिकता।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने राज्य में कमल खिलाने का मन पहले ही बना लिया है। कार्यक्रम में भाजपा के उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर, श्री पंकज चौधरी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री सत्या कुमार, श्री अमरपाल मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री शेषनारायण मिश्र, उत्तर प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री विजय बहादुर पाठक, राष्ट्रीय मीडिया सह–प्रमुख एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ संजय मयूख की उपस्थिति सांगठनिक ताने–बाने को मजबूती देती थी। मथुरा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी

आदित्यनाथ जी, झांसी में श्री राजनाथ सिंह जी, बिजनौर में श्री नितिन गडकरी जी, बलिया में श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और गाजीपुर में श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली अवध क्षेत्र की जन विश्वास यात्रा अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए लखनऊ के काकोरी में समाप्त होगी। जन विश्वास यात्राएं प्रदेश के सभी जिलों के 403 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेंगी। इस यात्रा के दौरान प्रदेश के लगभग 4 करोड़ लोगों से सीधा संपर्क का अनुमान था पर यात्राओं में जुट रही जनता ने पहले ही ये आंकड़े पीछे छोड़ दिये। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि प्रभु श्रीराम, भगवान् कृष्ण और महात्मा गौतम बुद्ध की धरती को नमन करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि लोगों के बीच में जाना, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना और जनता से किये गए हर वादे को जमीन पर उतार कर दिखाना, देश के लोकतंत्र में यह कार्य संस्कृति यदि किसी ने विकसित की है तो वह केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। पहले की संस्कृति तो ये थी कि लोगों को बाँट कर वोट बटोरो, झूठे वादे कर जनता को गुमराह करो, जनता में वैमनस्य पैदा करो और भाई–भाई को लड़ाओ। यह भारतीय जनता पार्टी है जो समर्पित भाव से जनता की सेवा कर रही है। बाकी हर पार्टियां वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दंश से ग्रसित है। पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक और जम्मू–कश्मीर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर लगभग सभी पार्टियां जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद या फिर संप्रदायवाद की ही राजनीति करती दिख रही है। जबकि, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर जन–जन के कल्याण के लिए कार्य कर रही है।

पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि खनन माफिया, भू–माफिया और अपराधियों ने सपा सरकार के समय किस तरह पूरे प्रदेश को अपने गिरफ्त में ले लिया था। उन सभी माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजने का और उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सभी योजनायें देश के सर्वांगीण विकास के लिए और जन–जन के कल्याण के लिए समर्पित है। चाहे आयुष्मान भारत हो, किसान सम्मान निधि हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना जो या कोई अन्य योजना – ये योजनायें देश के सभी लोगों के लिए हैं न कि केवल एक जाति या समुदाय विशेष के लिए। ये योजनायें देश के गरीबों के लिए हैं, पिछड़ों के लिए हैं, दलितों के लिये हैं, शोषितों और वंचितों के लिए हैं।

भाजपा की सरकार है तो विकास है, लोगों का सम्मान है, महिलाओं की सुरक्षा है। अन्य दलों की सरकार में इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती क्योंकि न तो उनकी ये सोच है और न ही ऐसा करने की उनकी मानसिकता। किसी राजनीतिक दल की सरकार ने पीछे क्या किया है, वही सपष्ट करता है कि उनकी सरकारें आगे भी क्या करेगी! हमें गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, कर के दिखाया। हमारी कार्य संस्कृति ही विकास की संस्कृति रही है। हमें इस पर गर्व है और हमारे विश्वास का आधार भी यही है।

आजकल लोग नए–नए नारे गढ़ कर नए–नए कलेवर में सामने आ रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सपा का कुशासन नहीं भूली है, सपा सरकार के समय का माफिया राज नहीं भूली है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं भूली है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजकल लोग नए–नए नारे गढ़ कर नए–नए कलेवर में सामने आ रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सपा का कुशासन नहीं भूली है, सपा सरकार के समय का माफिया राज नहीं भूली है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार नहीं भूली है। पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि खनन माफिया, भू–माफिया और अपराधियों ने सपा सरकार के समय किस तरह पूरे प्रदेश को अपने गिरफ्त में ले लिया था।

उन सभी माफियाओं और अपराधियों को जेल भेजने का और उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर खदेड़ने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश से माफियाओं और अपराधियों का सफाया किया है।

सपा और भ्रष्टाचार एवं अपराध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सपा सरकार के समय गोमती रिवर फ्रंट और यूटीलाइजेशन सर्टिफिकेट में करोड़ों का घपला उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। लैपटॉप वितरण में भी सपा की अखिलेश सरकार ने बड़ा घपला किया था। कई रिपोर्टों के अनुसार सपा सरकार ने खरीदी तो 14 लाख लैपटॉप थी लेकिन वितरण लगभग 6 लाख का ही हुआ। स्पष्ट है कि ये नई सपा नहीं है, वही सपा है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किये जाने की खबर पर समाजवादी पार्टी के नेता किस तरह अनैतिक बयान दे रहे हैं और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाय, कम है और इस पर तुर्रा यह कि अखिलेश यादव ऐसे शर्मनाक बयानों का खुल कर बचाव कर रहे हैं! समाजवादी पार्टी महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है।

> पहले की संस्कृति तो ये थी कि लोगों को बाँट कर वोट बटोरो, झूठे वादे कर जनता को गुमराह करो, उनमें वैमनस्य पैदा करो और भाई–भाई को लड़ाओ। यह भाजपा है जो समर्पित भाव से जनता की सेवा कर रही है। बाकी हर पार्टियां वंशवाद, जातिवाद, परिवारवाद और संप्रदायवाद के दंश से ग्रसित है।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विकास को जमीन पर उतारा है और प्रदेश के जन–जन तक पहुंचाया है। डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश में विकास की बहार आई है। एक ओर पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे और गंगा एक्सप्रेस–वे बन रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं। एक ओर रामायण सर्किट का निर्माण हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर बुद्ध सर्किट का निर्माण हो रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कभी बीमारू प्रदेश की सूची में रहने वाला उत्तर प्रदेश अब देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। आज उत्तर प्रदेश **"ईज ऑफ डूइंग बिजनेस"** में अच्छा कर रहा है। साथ ही, यह निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभर रहा है।

जब बड़े से बड़े देश कोरोना के सामने अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे, वहीं श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी देशवासियों को साथ लेते हुए कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। अब तक लगभग 137 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं।

उत्तर प्रदेश की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि ज़िंदा समाज वह होता है जो अच्छे काम करने वाले लोगों को शाबासी दे और काम न करने वाले लोगों को घर बिठाए। मुझे पूरा विश्वास है कि अवध की जनता काम न करने वाले लोगों को घर बिठाने का

काम करेगी और विकास के प्रति समर्पित रहने वाली भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार को पुनः भारी बहुमत से विजयी बनाएगी।

'काँग्रेस ने आजादी के मतवालों को भुला दिया : शिवराज सिंह चौहान

बलिया में शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले क्रांतिकारी, वीर सपूत मंगल पांडे, चितु पांडे और रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान को याद करते हुए कहा की यह बागी बलिया की धरती है, जिसने ऐसे राष्ट्र भक्तों को जन्म दिया, जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए बलिदान कर दिया। हमें देश की आजादी चांदी की तस्तरी में नहीं मिली बल्कि इसके लिए हजारों क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर किया है, लेकिन कांग्रेस ने भारत की आजादी में योगदान देने वाले वीर सावरकर, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कुंवर सिंह, तात्या टोपे जैसे अनेकों क्रांतिकारियों को भुला दिया, उनके इतिहास को भी ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया गया। मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हमारे अमर क्रांतिकारियों का खोया हुआ गौरव वापस दिलाने का काम किया और आजादी का 75 वां अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय लिया।

'भाजपा ने वंशवाद को निर्मूल किया'

केवल भारतीय जनता पार्टी ही हैं जहां वंशवाद से नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं मे से ही नेता खोज लिया जाता है, दीनदयाल जी, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, आडवाणी जी, अटल जी, मोदी जी,योगी जी ये सभी जनता के बीच से निकले हैं। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी ये सिर्फ वंशवाद की पोषक हैं, कांग्रेस में नेता हुए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तो वहीं समाजवादी पार्टी में नेता हुए मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेन्द्र यादव इत्यादि वर्षो तक इन परिवारों ने देश और प्रदेश पर राज किया उन्होंने कहा की यदि वंशवाद को पूरी तरह से निर्मूल किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज एक साधारण कार्यकर्ता भी प्रमुख पदों पर आसीन हो रहा है

'योगी सरकार में है कानून का राज'

उत्तर प्रदेश पिछली सरकारों में गुंडाराज के लिए बदनाम था आज उसी उत्तरप्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है, जिन गुंडों का बोलबाला था, आज वो सब जेलों में बंद हैं। यूपी में ७०० से ज्यादा दंगे अगर हुए तो सपा की सरकार में हुए, सैंकड़ों लोग अगर मरे तो अखिलेश की सरकार में मरे हैं, योगी जी की सरकार है तो दंगाई कहीं नहीं दिखते, योगी जी ने उन्हें जेल की हवा खिलाई। मोदीजी के मार्गदर्शन में और योगी सरकार की कुशलता से उत्तरप्रदेश खुशहाली और शांति की ओर अग्रसर है। हम कल्पना कर सकते हैं की अगर मोदी+योगी न होते तो न राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता और न ही काशी विश्वनाथ धाम को भव्य स्वरूप मिलता।

> आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छा कर रहा है। साथ ही, यह निवेश के सबसे अच्छे डेस्टिनेशन के तौर पर भी उभर रहा है।

गरीब हितैषी सरकार'

उत्तरप्रदेश की योगी और केंद्र में मोदी जी की सरकार गरीबों के कल्याण की सरकार है। कोविड संकट में गरीबों को किसी ने मुफ्त राशन दिया तो भाजपा की योगी और मोदी सरकार ने दिया, गरीबों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आयुष्मान जैसी योजना चलाई है जिसमें ५ लाख तक का इलाज फ्री में किया जा रहा है । 2024 तक सबको घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य मोदी सरकार है कोई भी गरीब बिना घर के नहीं रहेगा क्योंकि देश में मोदी और उतररप्रदेश में योगी जी की भाजपा सरकार है।

'डबल इंजन की सरकार'

उन्होंने डबल इंजन की सरकार के फायदे और उतररप्रदेश को मिली सौगातें बताते हुए कहा की मोदी+योगी मतलब–86 लाख किसानों का 36 हजार करोड़ का कर्जा माफ, किसानों को 1.44 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को 2376 करोड़ का लाभ,माफियों द्वारा अवैध ढंग से कब्जा की गई 1866 करोड़ की संपत्ति जब्त, 150 अपराधी ढेर, 44759 गुंडे, बदमाश गिरफ्तार, 11 हजार 864 इनामी अपराधियों की

गिरफ्तारी, जबरन धर्म परिवर्तन रोकने, उत्तर प्रदेश विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन कानून, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 341 किमी का पूर्वांचल एक्सप्रेस,2.61 करोड़ शौचालयों का निर्माण, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड–2020 में यूपी को प्रथम पुरस्कार,बेटियों को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभान्वित, 4.50 लाख युवाओं को सरकार नौकरी, 3.50 लाख युवाओं की संविदा पर नियुक्ति संभव हो सकी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है ।

'राहुल गांधी हिन्दुत्व की परिभाषा देते फिर रहे हैं'

वर्तमान राजनीति में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि जो लोग हिंदु को सांप्रदायिक कहते थे वो भी हिंदु हिंदु जप रहे हैं। आजकल राहुल गांधी हिन्दुत्व की परिभाषा देते फिरते हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हिन्दुत्व क्या है!

"अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम" यह हिन्दुत्व है! "वसुधैव कुटुंबकम" यह हिन्दुत्व है! अब सत्ता के लिए उन्हें हिन्दुत्व याद या रहा है

'सपा सरकार में करोड़ों के घोटाले'

सपा सरकार ने उत्तरप्रदेश को तबाह कर दिया था, समाजवाद के नाम पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूटमार ही प्रदेश की पहचान बन गई थी, अखिलेश सरकार ने अनेकों घोटाले किए समाजवादी पेंशन 10 अरब रुपये की और उसमें चार लाख से अधिक लोग थे ही नहीं, सभी घोटालों की जांच चल रही है। एम्बुलेंस के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला किया। उन्होंने कहा की अखिलेश यादव का गठबंधन, गठबंधन नहीं, ठगबंधन है! बबुआ ने पिताजी को ठगा, चचा शिवपाल को ठगा..अब जनता को ठगने निकला है। उन्होंने कहा की मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में केवल हिंदुस्तान नहीं, ब ल्कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश बनेगा। जब केन्द्र में और राज्य में भाजपा की सरकार हो तो विकास की गति भी डबल हो जाती है, जैसी आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत भाजपा राज्यों में हो रही है।

'मोदी और योगी का मतलब'

जिस ब्रिटेन ने हम पर वर्षों तक हुकूमत की, आज उन्हीं का प्रधानमंत्री कहता है कि विश्व एक, ऊर्जा का स्रोत सूर्य एक, विश्व में नरेंद्र मोदी भी एक है। यह स्थिति यूं ही नहीं बनी, यह मोदी जी के विराट व्यक्तित्व का प्रमाण है, उन्होंने मोदी और योगी का अर्थ बताते हुए कहा कि – मोदी का मतलब M – मजबूत नेतृत्व, O – ओजपूर्ण व्यक्तित्व, D – दृढ़ निश्चयी I – ईश्वर का वरदान हैं तो वहीं योगी का मतलब Y– योग्य, O – ओजस्वी, G – गतिशील, I – ईमानदार व्यक्तिव जो प्रदेश और देश में डबल इंजन रूपी सरकार से विकास का कायाकल्प कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीते पौने पांच वर्षों में एक नए उत्तर प्रदेश का निर्माण हुआ है। यह नया यूपी एक ओर जहां अपने आस्था के मानबिन्दुओं का निर्माण कराएगा, वहीं अपराधी–माफियाओं पर बुलडोजर भी चलाएगा। उन्होंने कहा है कि 2017 के पहले हिन्दू पीड़ित था

'गरीब का घर बनना हमारे लिए रामराज्य': योगी

और व्यापारी प्रताड़ित। आज के यूपी में पेशेवर माफिया पलायन को मजबूर हो गए हैं।

मथुरा में श्रीबांकेबिहारी जी के दर्शन–पूजन के बाद जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि सपा, बसपा और कांग्रेस को दंगाइयों को गले लगाना, आतंकवादियों पर मुकदमे हटाना, विकास कार्यों में लूट–खसोट, गौ–तस्करों को प्रोत्साहन और आस्था के साथ खिलवाड़ करना पसंद है। ऐसे में जब आज मथुरा–वृंदावन को नगर निगम बनाया जा रहा, ब्रज तीर्थ विकास परिषद बन रहा, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की डबल डोज मिल रही तो इन संकुचित सोच वाली पार्टियों को कुछ नहीं सुहा रहा। उन्होंने कहा कि सपा शासन काल मे हुए जवाहर बाग और कोसीकलां दंगे की दुःखद घटना सभी को याद है। वर्तमान राज्य सरकार के पौने पांच वर्ष पूरे होने पर सभी को बधाई–आभार देते हुए उन्होंने कहा कि इन पौने पांच सालों में पूरे प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ।

उत्साह और उमंग से भरे लाखों की संख्या में उमड़े लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने काशी विश्वनाथ धाम पुनरोद्धार, अयोध्या में जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण, विंध्यवासिनी धाम कॉरिडोर, मथुरा–वृंदावन को तीर्थ स्थल घोषित करने जैसे जन भावनाओं से जुड़े विषयों की चर्चा की और पूछा कि क्या सपा, बसपा अथवा कांग्रेस की सरकारों से ऐसा करने की उम्मीद की जा सकती थी..? इस पर लोगों ने उत्तर 'नहीं' में दिया। सीएम ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार बनने से पहले इन पार्टियों में 'टोपी' पहनने की होड़ लगती थी। अयोध्या, काशी और मथुरा तो इनके लिए अछूत थी, आज यही लोग हमारे इन पावन स्थलों के चक्कर काटते नहीं थक रहे।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा भाजपा ने जो कहा, वो किया। हमारे लिए गरीबों को मुफ्त मकान मिलना रामराज्य है, हर घर शौचालय की सुविधा रामराज्य है, हर गरीब को 05 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर मिलना रामराज्य है। यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज हो रहा है। उन्होंने जनसमुदाय से कहा कि प्रयागराज में स्वच्छता कर्मियों के पैर धोना और काशी में शिव की पूजा के बाद श्रमिकों पर पुष्पवर्षा आजाद भारत की ऐतिहासिक घटना है। विपक्ष पर तंज करते हुए सीएम ने कहा आज तक दूसरे दलों के नेताओं के अपने माँ–बाप के पैर धुलते तो किसी ने देखा नहीं तो एक प्रधानमंत्री के ऐसा करने की कल्पना शायद ही किसी ने की हो। सच्चे अर्थों में यही स्वतंत्रता है। यही रामराज्य है।

'एक झटके में कूड़े के ढेर में फेंक दिया अनुच्छेद 370'

सीएम योगी ने कहा कि मथुरा हमारे दिग्दर्शक पंडित

दीनदयाल जी की जन्मभूमि है। जनसंघ के संस्थापक काल से ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 'एक देश में दो विधान–दो निशान–दो प्रधान' का विरोध किया था। दशकों की प्रतीक्षा के बाद जब मोदी सरकार बनी तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने एक झटके में अनुच्छेद 370 को कूड़े के ढेर में फेंक दिया और इस तरह डॉ. मुखर्जी का संकल्प पूरा हुआ। हाल ही में आयकर की टीम द्वारा प्रदेश में कुछ बड़े घरानों पर की गई छापेमारी का संदर्भ देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आयकर की छापेमारी से सपा नेताओं को बड़ी चिंता हो रही है। इन्हीं के शासनकाल में कुछ लोगों ने अवैध ढंग से अकूत दौलत कमाई की। मुख्यमंत्री योगी ने वृद्धवस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, प्रधान, रोज़गार सेवक, आशा कार्यकत्रियों आदि के मानदेय में हुई ऐतिहासिक बढ़ोतरी जिक्र करते हुए प्रदेश के विकास में सभी के योगदान की सराहना भी की।

स्मृति ईरानी ने भारत माता की जय से अपने उद्बोधन का शुभारंभ करते हुए गाजीपुर की बलिदानी धरती को प्रणाम किया। कहा कि यह यात्रा जनता के प्रति भाजपा के विश्वास को भावना को समर्पित कर गांव–गांव, शहर–शहर जाएगी। आह्वान किया कि जहां से यात्रा गुजरे तो याद दिलाओ कि भूलना मत वो मंजर जब साइकिल के साथ वो हाथ का पंजा जुड़ा था और वो हाथ हमारी मां–बहनों का आंचल उड़ाया करता था। भूलना मत उप्र का वो मंजर जब गरीब की बेटियों पर लाठी चलाई जाती थी, सरकारी नौकरी नेता अपनी जेब में रखते थे और भाई–भतीजे को बांटते थे।

गाजीपुर के भाइयों भूलना मत वो मंजर जब किसान खाद के लिए लड़ता था और किसानों पर लाठी चलाने से सपा का कोई भी नेता डरता नहीं था। भूलना मत, गरीबों को लूट–लूट कर गुंडे–माफिया अपना आलीशान महल बनाते थे। कहा कि जिनकी यादशात कमजोर है, उनसे कहना चाहती हूं गाजीपुर में भी बुल्डोजर चलाया गया माफिया के छाती पर। दर्द हुआ तो अखिलेश को हुआ। मैं उनसे पूछता चाहती हूं, दर्द तब क्यों नहीं हुआ, जब जनता लूटी जा रही थी। दर्द तब क्यों नहीं हुआ जब बहनों की इज्जत लूटी जा रही थी, दर्द तब क्यों नहीं हुआ, जब माफिया एके–47 लेकर भयभीत कर रहे थे। तब जनता के लिए दर्द क्यों नहीं हुआ।

इन यात्राओं ने पूरे प्रदेश के जनमानस को झकझोर दिया है, पूरे प्रदेश में दिनभर में 6 यात्राओं द्वारा सैकड़ों स्वागत सभाएं लाखों लोगों से संवाद, सैकड़ों की यात्रा ने पूरे कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया जिसका परिणाम है जनता कार्यकर्ताओं के विश्वास में अपार वृद्धि जो भाजपा को विजय श्री दिलाते हुए 300 के पार पहुंचायेगा।

कार्यकर्ता अपने बूथ को जीतने के लिए पन्ना प्रमुख से निरन्तर सम्पर्क संवाद कर रहा है, जाड़े के दिन सर्द रातों में भी अगर कार्यकर्ता इन यात्राओं में अपने नेता के स्वागत उनके विचारों को सुनने के लिए खड़ा मिल रहा है, तो यह शुभ संकेत हैं। जो पार्टी को ऐतिहासिक विजय की ओर ले जायेगा।

भारत- भारतीयता के प्रकाशपुंज

डॉ. हरनाम सिंह

भारत भारतीयता के ऐसे प्रकाशपुंज जिन्होंने अपनी आभा और प्रतिभा से भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को पुनर्स्थापित व प्रकाशित किया है "भारत रत्न" पंडित मदन मोहन मालवीय जी एवं पंडित अटल बिहारी बाजपेयी जी ने । "हम जिएँगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए" के उद्घोषक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी जिनका कहना था कि मुझे इत्र की गंध पसंद नहीं, मुझे शील की गंध, चरित्र की गंध, धर्म की गंध, सबसे अधिक विश्वविद्यालय की सुगंध पसंद है। भारत रत्न को सम्मानित करनेवाले अटल बिहारी वाजपेयी जी जिनका सन्देश था कि हमें नया भारत नहीं बनाना पर इस प्राचीन देश को आधुनिक समय की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। भारत रत्न को सम्मानित करनेवाले पं. मदन मोहन मालवीय जी व अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमेशा देश के लिए प्राण – प्रण से लगे रहें। भारतीय ज्ञान परंपरा की गहराई, मानवता, समग्रता एवं एकात्मता जैसे मूल्यों के संवाहक इन दोनों विभूतियों की कृतिया सदैव आचरणीय रहेगी। मानवीय मूल्यों में निस्वार्थता, शुद्धता, सहानुभूति, प्रेम,कर्तव्यपरायणता आदि गुणों के बीजारोपण कर उन्हें निरंतर सीखने का संपूर्ण दायित्व समाज का है, ताकि मानवता से ओतप्रोत एक संस्कारी मनुष्य के साथ सम्यक समाज का निर्माण हो सके। प्राचीन धर्म की शिक्षा भी प्रत्येक मनुष्य को स्वयं में एक समष्टि इकाई समझकर लोक – कल्याण और लोक संग्रह को परम – पुरुषार्थ समझकर सशक्त राष्ट्र के निर्माण हेतु प्रोत्साहित करती रही है। जब तक मनुष्य में आत्मिक एवं नैतिक बल नहीं होगा, तब तक वह भी सच्चे अर्थों में समृद्ध नहीं हो सकता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने विद्यार्थियों को संदेश दिया था–

"सत्येन ब्रह्मचर्येण व्यायामेनाथ विद्यया।
देशभक्त्यात्मत्यागेन सम्मानार्हः सदा भव।।

अर्थात् सत्य पालन, आत्म संयम या ब्रह्मचर्य पालन, शारीरिक व्यायाम, शिक्षा, देश भक्ति तथा आत्मत्याग द्वारा सदा ही सम्मान पाने योग्य बनो। भारत में शिक्षा अंतरज्योति और शक्ति का स्रोत मानी जाती रही है, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक शक्तियों के संतुलित विकास से हमारे

स्वभाव में परिवर्तन लाती है तथा उसे श्रेष्ठ बनाती है। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम समाज के एक विनीत और उपयोगी नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। इन दोनों विभूतियों के आदर्शों को आत्मसात करना व्यक्तित्व के विकास की धुरी है। इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीय युवा पीढ़ी में देशप्रेम, राष्ट्रीयता और संपूर्ण मानवता के प्रति प्रेम के मूल्यों की स्थापना करना है।

इनके द्वारा प्रतिपादीत मानदंडों को अनुगमन करते हुए कौशल– ज्ञान की लौ को देश के कोने कोने फैलाने का संकल्प लेना होगा । बेहद खास फिर भी साधारण, राजनीति से सत्ता मिली पर सत्ता की राजनीति से दूर, कूटनीति में पारंगत पर कवि हृदय, कड़े फैसले लेने का जज़्बा पर काव्यात्मक अंदाज़, सबको साथ लेकर चलने का हुनर रखने वाले अटल जी ने कहा था–

भारत वंदन की भूमि है, अभिनन्दन की भूमि है।
यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है।
इसका कंकर–कंकर शंकर है, इसका बिन्दु–बिन्दु गंगाजल है।
हम जियेंगे तो इसके लिये, मरेंगे तो इसके लिये।
जरूरी यह है कि ऊँचाई के साथ विस्तार भी हो
जिससे मनुष्य ठूंट सा खड़ा न रहे
औरों से घुले–मिले –किसी को साथ ले
किसी के संग चले !!
धरती को बौनों की नहीं
ऊँचे कद के इन्सानों की जरूरत है
इतने ऊँचे कि आसमान छू लें
नये नक्षत्रों में –प्रतिभा की बीज बो लें !!
किन्तु इतने ऊँचे भी नहीं
कि पाँव तले दूब ही न जमे
कोई कांटा न चुभे
कोई कलि न खिले
न वसंत हो, न पतझड़
हों सिर्फ ऊँचाई का अंधड़
हो मात्र अकेलापन का सन्नाटा !! मेरे प्रभु!
मुझे इतनी ऊँचाई कभी मत देना
गैरों को गले न लगा सकूँ
इतनी रुखाई कभी मत देना!!■

अटल संकल्प

सुशासन को साकार करती सरकार

श्री मानवेन्द्र प्रताप सिंह

भारतीय राजनीति के अजातशत्रु कहे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी आजाद भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिनका जुड़ाव सीधे लोगों के दिलों से था अटल बिहारी वाजपेयी ने दुनिया को दिखाया था कि सरकार में रहते किस तरह से सुशासन दिया जा सकता है। साल 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा ही बदल गई थी. उन्होंने 1991 में पी.वी. नरसिंह राव सरकार द्वारा पेश किए गए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाया अटल के कार्यकाल के दौरान बेहतर आर्थिक सुधारों का परिणाम था कि जब 2004 में मनमोहन सिंह ने पदभार संभाला, तो उन्हें बेहतर अर्थव्यवस्था मिली. उस समय सकल घरेलू उत्पाद की दर 8 प्रतिशत से अधिक थी, जबकि महंगाई दर 4 प्रतिशत नीचे और मुद्रास्फीति भी बेहतर स्थिति में थी तीन बार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए थे जिन्हें आज भी हर भारतीय याद करता है. 1998 में उन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण करवाकर दुनिया को यह संदेश दे दिया था कि अब भारत किसी से डरने वाला नहीं है. अटल ने अपने शासनकाल के दौरान कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो मजबूती मिली ही साथ में हर भारतीय को उसका लाभ आज भी मिल रहा है अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के हर नागरिक को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी कदम उठाए और ऐसी नीतियां व योजनाएं बनाईं जिससे अनदेखी का शिकार रहे समाज के निम्न वर्ग को लाभ मिल सके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अटल बिहारी वाजपेयी की दिखाई राह पर चल रहे हं9 और उनका भी एकमात्र उद्देश्य देश के विभिन्न वर्गों तक सरकारी योजनाओं को लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। साथ ही पुरे विश्व में नए भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए दृढ संकल्पित है

स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना

अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी उपलब्धियों में उनकी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सबसे ऊपर रखा जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने चेन्नै, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को हाईवे नेटवर्क से कनेक्ट किया, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए गांवों को पक्की सड़कों के जरिए शहरों से जोड़ा गया। ये योजनाएं सफल रहीं और देश के आर्थिक विकास में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल हाईवे के निर्माण के साथ–साथ गांवों को भी सड़कों से जोड़ने का काम किया. मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान नेशनल हाईवे के निर्माण पर काफी बल दिया गया. इसी के कारण अभी देश में लगभग 23 एक्सप्रेस्वे बनाने का लक्ष्य रखा गया है. एक्सप्रेस–वे निर्माण में तेजी को हम इसी आंकड़ों से समझ सकते हैं कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रतिदिन 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जबकि यूपीए सरकार के दौरान इसके निर्माण का एवरेज लगभग 13 किलोमीटर प्रति दिन था मई 2013 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–2 की शुरुआत हुई जिसके तहत 50,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें से अभी तक 49000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और 500 से अधिक पुलों का निर्माण किया जा चुका है

सर्व शिक्षा अभियान

अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी. यह भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम था , जिसके तहत 6–14 साल के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान को मौलिक अधिकार बनाया गया था. इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालयों के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ सामाजिक, क्षेत्रीय और लिंग संबंधी अंतरालों के अंतर को

खत्म करना था. मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को अगले 5 साल तक जारी रखने के लिए मंजूरी दी है. अभियान के तहत अब तीन साल की उम्र से ही बच्चों को खेल का माध्यम से सिखाने पर जोर दिया जाएगा. अब सरकारी स्कूलों में भी प्ले स्कूल दिखाई देने लगेंगे. दरअसल समग्र शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा. कक्षा 6 से आठवीं तक के बच्चों का विभिन्न कौशल से परिचय कराया जाएगा, जबकि कक्षा 9 से 12 वीं के बच्चों में उनकी रुचि के कौशल के प्रति फोकस किया जाएगा।

दूरसंचार क्रांति

अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ही अपनी नई टेलिकॉम पॉलिसी के तहत टेलिकॉम फर्म्स के लिए एक तय लाइसेंस फीस हटाकर रेवन्यू शेयरिंग की व्यवस्था लेकर लाई थी । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'गति शक्ति' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में यह एक प्रयास है. उन्होंने भारत को एक बड़ा विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा में सरकार की प्राथमिकता तय की है एक समय था जब भारत चीन से मोबाइल का आयात करता था परन्तु आज का युवा भारत इनोवेशन में अपनी धमक दिखाते हुए पूरी दुनिया में मोबाइल का निर्यात करना शुरू कर दिया है

वैश्विक स्थर के संबंधो को मजबूत किया

अटल बिहारी वाजपेयी कार्यकाल के दौरान, भारत ने अपने व्यापार में सुधार किया. 2000 में, उन्होंने शीत युद्ध के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को आमंत्रित भी किया था. उन्होंने सीमावर्ती आतंकवाद और कश्मीर पर चर्चा के लिए जुलाई, 2001 में दो दिवसीय आगरा शिखर सम्मेलन की बैठक के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भारत में आमंत्रित किया था. इसके अलावा, अटल जी ने 19 फरवरी 1999 को ऐतिहासिक दिल्ली–लाहौर बस के उद्घाटन के साथ भारत और पाकिस्तान के बीच सड़क कनेक्टिविटी को ग्रीन सिग्नल दिया था. मोदी सरकार ने विदेश नीति को आगे बढ़ाते हुए 2014 से विदेश दौरे करके भारत को विदेशी मोर्चे पर मजबूत किया जिसकी वजह से आज भारत लगातार अपने विरोधियो को कमजोर साबित कर रहा है अभी हॉल में ही भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन करके अपनी वैश्विक पहचान को और मजबूत किया।

विज्ञान और अनुसंधान

लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था वाजपेयी जी ने इसके साथ जय विज्ञान जोड़ा और नरेन्द्र मोदी ने इसके साथ जय अनुसंधान जोड़ा कर इसे अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा करके इसकी सार्थकता को और मजबूत कर दिया मोदी सरकार ने लगातार इस विचार पर बल दिया कि देश में दशकों से चली आ रही मानवीय समस्याओं के समाधान के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करते हुए देश कैसे सेंसर, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी खोज का पैकेज बनाकर किसानों के लिए कैसे बेहतरीन खोज कर सकता है, कोरोना काल के दौरान भारत ने देश में अब तक 135 करोड़ कोरोना टीके की खुराकलगा कर विज्ञान और इनोवेशन का परिचय दिया।

नए विभाग कर निर्माण

अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को जनजातीय मामलों के मंत्रालय, उत्तर–पूर्व क्षेत्र विभाग और सामाजिक कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय मंत्रालय में परिवर्तित करने के लिए नए विभागों के निर्माण के लिए भी श्रेय दिया जाता है.उसी प्रकार से मोदी सरकार ने भी जलशक्ति सहकारिता को अलग से नया सहकारिता विभाग बना कर भारतीय अर्थव्यवस्था को नयी उचाई पर ले जाने के लिए अपनी सरकार के दृढ़ता को प्रदर्शित किया और साथ ही सहकारिता से जुड़े देश के 8.5 करोड़ लोगो के लिए नयी आस पैदा किया।

मैन्यूफैक्चरिंग हब

कोरोना काल के दौरान भारत ने अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पीछे दिया है भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाने के लिए आत्मनिर्भर और पीआईएल योजना ने भी अपना असर दिखाना शुरू किया है. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों में नवंबर माह में देश के निर्यात में तेज इजाफा देखने को मिला है। भारत में आईफोन असेंबल करने वाली ताईवान की कंपनी विस्ट्रॉन कॉप अब लैपटॉप, मोबाइल, आईटी उत्पाद बनाएगी।

युद्ध में विजय

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान हुए करगिल युद्ध में भारत ने विजय हासिल की और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत झुकने वालों में से नहीं है उरी हमले के बाद मोदी सरकार द्वारा कठोर निर्णय लेते हुए बालाकोट में एयरस्ट्राइक करके सरकार ने दृढ़ इच्छा दिखाते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया और गलवान घाटी भारतीय सैनिको ने अदम्य सहस दिखाते हुए चीन के 40 सैनिको को मार गिराया और भारत के आत्म गौरव को पुर्नस्थापित किया।■

''अंत्योदय'' अंतिम व्यक्ति का कल्याण

श्री नरेन्द्र मोदी

1940 के दशक के शुरूआती वर्षों में भारत की स्थिति की कल्पना कीजिए...आजादी बहुत नजदीक थी, लेकिन तब भी दूर दिखती थी, दुनिया खतरनाक तरीके से युद्ध में घिरी हुई थी और हर तरफ अनिश्चितता का वातावरण था...!

ऐसे समय में, ग्वालियर के एक युवा ने अपना जीवन देश–सेवा और अपने देशवासियों की भलाई के लिए समर्पित करने का फैसला किया...!

राष्ट्र निर्माण के इसी लक्ष्य ने अटलजी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल होने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपना जीवन संघ को समर्पित कर दिया।

आने वाले वर्षों में उनका ये संकल्प और भी मजबूत होता चला गया, लेकिन जिस मार्ग पर वो चल रहे थे, उसकी अपनी चुनौतियां थीं...!

ये अटल जी का ही महान व्यक्तित्व था कि इतिहास के अलग–अलग पड़ाव पर देश का राजनीतिक वातावरण प्रतिकूल होते हुए भी वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए..!

अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में, अटलजी ने ज्यादातर समय विपक्ष में ही बिताया, माहौल ऐसा था कि देश के राजनीतिक विमर्श में एक ही पार्टी और एक ही परिवार का दबदबा था...ऐसे में कई मौकों पर राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दे उठाने के लिए अटलजी के पास गिने–चुने सहयोगी ही होते थे, बावजूद इसके, अटलजी की आवाज सत्ता को नींद से जगाती रही, राष्ट्र निर्माण के पथ पर लौटाती रही..!

अटल जी की सभी कार्यों की प्रेरणा अंत्योदय था।

महत्वपूर्ण ये नहीं था कि वो राजनीति के गलियारे में किस तरफ बैठे थे, बल्कि महत्त्व, भारत के पुनर्निर्माण में उनकी प्रतिबद्धता का था, यही वजह है कि अटल जी भारत के अब तक के सबसे उत्कृष्ट सांसदों में से एक गिने जाते हैं... वो ऐसे मुद्दे उठाते थे जो आम तौर पर उपेक्षित, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थे, अटलजी इन मुद्दों पर संवाद करने से कभी नहीं हिचकिचाए, संसद में वो बहुत मुखर आलोचक थे, लेकिन साथ ही बहुत अहम सहयोगी भी थे..!

जब भी ऐसी परिस्थिति आई, जिसमें देश के व्यापक हित में कभी सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ा, तो अटल जी ने खुशी–खुशी इस काम को भी किया।

इसलिए, जब 1993 में पाकिस्तान को कूटनीतिक जवाब देने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव ने अटल जी को चुना, तो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें तब संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधिमंडल की अगुआई करने के लिए चुना गया था...तब दुनिया भर में लोग ये जानकर हैरान रह गए थे कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता, भारत के नागरिकों और सरकार की तरफ से बोल रहा है, उन्होंने जिनेवा में भारत की कई बड़ी कूटनीतिक विजयों में भी अपनी विशेष भूमिका निभाई..!

अटलजी को एक बार नहीं, बल्कि कई बार राजनीतिक छुआछूत का दंश झेलना पड़ा, 1979 में जनता सरकार दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर अस्थिरता के भंवर में फंसी, लेकिन अटलजी कभी नहीं डिगे...!

इसके 17 साल बाद, 1996 में पूरे देश ने देखा कि किस तरह सभी पार्टियां अटल जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिये एकजुट हो गईं, लेकिन 1998 में दोबारा अटलजी की वापसी हुई, 1999 में भले ही अवसरवादी गठबंधन उनकी सरकार को हटाने में सफल हो गया, लेकिन लोगों ने एक बार फिर चुनाव में उनको आशीर्वाद दिया और वो प्रधानमंत्री बने...!

इस दौरान, क्षणिक लाभ के लिए, कई अवसरों पर विचारधारा से समझौता करने का भी दबाव पड़ा, लेकिन अटलजी तो अटलजी थे, वो अपनी आखिरी सांस तक उसी पथ पर चलते रहे, जिसका संकल्प उन्होंने दशकों पहले ले लिया था..!

अटल जी स्वभाव से बहुत विनम्र और सहृदय थे, लेकिन जब भारत को उकसाया गया तो अटलजी ने ये भी दिखा दिया कि वो चट्टान से भी दृढ़ हैं और ऐसी हरकतों को हल्के में नहीं लेते...हमारे पड़ोसी ने एक नहीं, दो बार अटलजी का यही दृढ़ रूप देखा, पहला 1999 में कारगिल युद्ध के समय और दूसरी बार 2001 में संसद पर आतंकवादी हमले के दौरान...दोनों अवसरों पर अटलजी ने ये साफ संदेश दिया कि शांति की भूमि भारत को अगर उकसाया गया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा...!

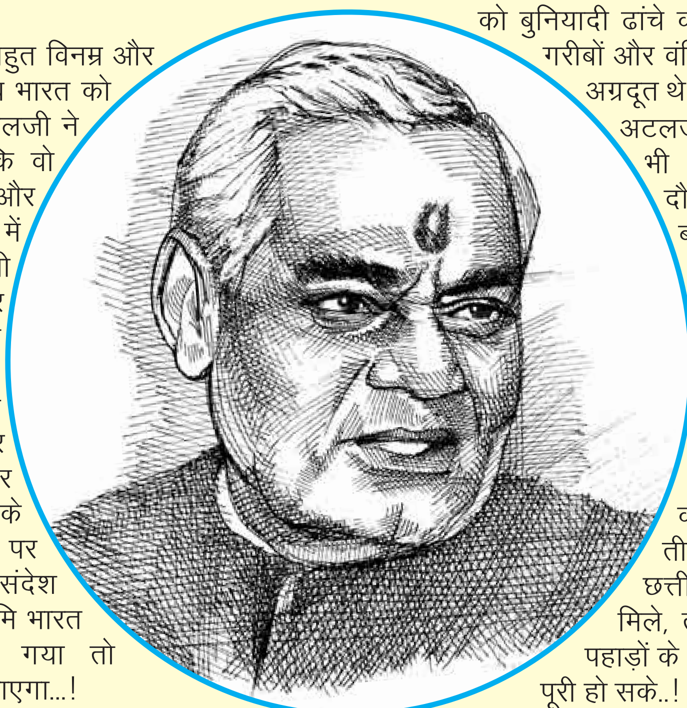

ये अटलजी की प्रतिबद्धता थी कि 11 मई 1998 को भारत आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर देश बन गया, अटलजी ने जैसे ही ये घोषणा की, वैसे ही भारत को कड़े आर्थिक प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय दबाव झेलने पड़े... परंपरागत सोच इस दबाव के आगे घुटने टेक देती, लेकिन अटलजी ने दो दिन बाद ही, 13 मई को दूसरे दौर के परीक्षण का आदेश दे दिया.।

ये दिखाता है कि जब राष्ट्र के राजनीतिक नेतृत्व का संकल्प अटल होता है, तो वो दुनिया के सामने न सिर्फ सिर उठाकर खड़ा रह सकता है बल्कि भारत की आवाज को दुनिया की प्रभावशाली आवाज भी बना देता है, उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि इन प्रतिबंधों का असर गरीबों पर ना पडेद और भारत के आर्थिक विकास की रफ्तार जारी रहे..!

प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी के कामकाज को देश में समाज के सभी वर्ग गर्व के साथ याद करते हैं...!

उनकी सरकार ने भारत के 21वीं सदी में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया, उनके कार्यकाल में भारत के आर्थिक विकास ने नई ऊंचाइयां छुईं...उन्होंने भारत को आधुनिकतम राजमार्ग, सशक्त टेलीकॉम सैक्टर, एविएशन और बंदरगाह समेत कई क्षेत्र में अगली पीढ़ी को बुनियादी ढांचे की सौगात दी, अटलजी गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण के अग्रदूत थे...!

अटलजी के कार्यकाल की ये भी विशेषता रही कि उस दौरान कुछ लोगों के बजाय, वृहत्तर समाज को समृद्धि में शामिल होने का मौका मिला, इसी सोच के साथ उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता का एक अलग मंत्रालय भी बनाया...उनके कार्यकाल में भारत को तीन नए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड मिले, ताकि आदिवासियों और पहाड़ों के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी हो सके..!

अटलजी के इन सभी कार्यों की प्रेरणा था–अंत्योदय का मंत्र, अंत्योदय मतलब कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण..!

अब, हमारे सामने अटलजी के सपनों को सच करने की जिम्मेदारी है, उनका सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व, समावेशी सोच और सहज–सरल जीवन और हमें न्यू इंडिया बनाने के लिए दिन–रात कार्य करने की प्रेरणा देता है... भारत के लिए वैश्विक नेतृत्व और श्रेष्ठता की प्राप्ति का यही रास्ता है..!!

युग पुरुष को जन्मजयंती पर शत् शत् नमन..!

सुशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश

श्री सौरभ चन्द्र पाण्डेय

माननीय नरेन्द्र मोदी जी नीत केंद्र सरकार ने सुशासन के पैरोकार भारतीय राजनीति के अजातशत्रु भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और 25 नवंबर 2014 को वाराणसी से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सुशासन दिवस के लिए इस दिन को सबसे उपयुक्त दिन कहा। माननीय नरेन्द्र मोदी जी नीत भारत सरकार ने देश और समाज के हर वर्ग की खुशहाली, प्रसन्नता और उनके हितार्थ विकास केन्द्रित शासन प्रणाली को संचालित करते हुए सुशासन के दैवीय लक्ष्यों को पाने का सपना देखा।

26 मई 2014 को भारतवर्ष की राजनीति में केन्द्रीय शासन के स्तर पर एक अभूतपूर्व परिवर्तन परिलक्षित हुआ एवं माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में नवीन सरकार का गठन हुआ। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार केंद्र की सत्ता में अपने दम पर सरकार अवश्य बनाई परंतु भाजपा को इस उन्नति के शीर्ष शिखर पर पहुंचाने में जिन नेताओं ने अपना सर्वस्व समर्पित किया, उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, एम वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली सरीखे कुशल नेता रहे, जिन्होंने भारतीय राजनीति के सरोवर में कमल खिलाने हेतु अपने स्वेद से भाजपा को सींचा।

सरकार बनने के बाद माननीय नरेन्द्र मोदी जी नीत केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत देश में "सबका साथ, सबका विकास" के मूल मंत्र को धारित करते हुए नवीन राष्ट्रीय विकास लक्ष्य संकल्पित किए गए, जिससे समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के साथ हर वर्ग के लिए सर्वांगीण एवं समरस विकास सुनिश्चित किया जा सके और देश हर क्षेत्र में अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए विकास की ओर उत्तरोत्तर उन्मुख हो।

भारतीय जनता पार्टी की रामराज्य की संकल्पना और राष्ट्रवाद की अवधारणा को केंद्र में रखकर साल 2014 में

भारत के संदर्भ में सुशासन का अर्थ जनसहभाग लेकर, जनविश्वास को जीतते हुए सभी के प्रयास से ऐसे भारतवर्ष का निर्माण करना है, जहां हर नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों का सम्यक अभ्यास करे। शासन–प्रशासन, जनता के हितार्थ, स्वहित से पहले, जनसरोकरों और जन आवश्यक्ताओं को महत्व और सम्मान दे। सुशासन, जहां कानून के राज में वर्ग, जाति, पंथ, संप्रदाय के समावेशी उत्थान को साकार करता है वहीं नागरिकों की राष्ट्र के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना को भी आकार देता है। सुशासन का लक्ष्य राष्ट्रहित में शासन–प्रशासन और आम जनमानस, सभी को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाते हुए वंचितों एवं शोषितों को आदर तथा सम्मान देकर समावेशी समाज के निर्माण में योगदान देना है।

सुशासन दिवस को मनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी सरकार का केंद्रीय विचार, देश के नागरिकों और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना है। इसके अतिरिक्त नागरिकों एवं संस्थाओं को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का सम्यक अभ्यास करते हुए "राष्ट्र सर्वोपरि" का विचार केंद्र में रखकर देश के प्रति अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित करना है।

भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय पार्टी

अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति और संगठन की सामूहिक चेतना के बलबूते उत्तर प्रदेश में लंबा वनवास खत्म किया। केंद्रीय नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ जी के हाथों में प्रदेश की कमान थमाई। योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम बनते ही भारतीय जनता पार्टी की नीति के अनुरूप सरकार संचालन प्रारम्भ किया और पार्टी के आदर्श पुरुषों के आशीर्वाद के साथ सुशासन की ओर अपने कदम बढ़ाए। योगी आदित्यानाथ जी ने राज्य की खुशहाली और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन शुरू किया। राज्य के नागरिकों के बहुमुखी विकास के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार निरन्तर अनेकों योजनाओं के माध्यम से जनहित के काम कर रही है एवं उत्तर प्रदेश में सुशासमन के लक्ष्य की ओर अनवरत बढ़ रही है। यही कारण है कि शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसस वे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी जी के शासन को उत्तर प्रदेश के लिए **UP+YOGI=UPYOGI (उपयोगी)** शासन के रूप में परिभाषित किया।

उत्तर प्रदेश में सुशासन की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए माननीय योगी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने जनहित हेतु अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को स्वयं का विकास करने हेतु पर्याप्त संसाधन एवं अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सुशासन का महत्वपूर्ण आधार प्रत्येक जीवधारी हेतु राज्य को तदानुभूति पूर्ण बनाना है। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना के द्वारा प्रदेश में गोवंश के संरक्षण एवं अभिवृद्धि हेतु गोपालकों को अनुदान मुहैया कराया जा रहा है। यह दर्शाता है कि योगी जी नीत राज्य सरकार ना केवल मनुष्यों हेतु अपितु पशुओं के प्रति भी सहानुभूति रखती है।

युवा किसी भी समाज का परिवर्तन पुरोधा होता है यदि युवा स्पष्ट लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो तो उस राष्ट्र एवं समाज को स्व परिमार्जन हेतु अधिक प्रतिक्षा नहीं करनी होती। उत्तर प्रदेश में युवाओं को सुशासन की प्रक्रिया में भागीदार बनाने हेतु प्रदेश की योगी सरकार ने युवा विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क टेबलेट एवं स्मार्ट फोन योजना, छात्रवृत्ति योजना, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कौशल विकास योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एवं शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के माध्यम से सुशासन का अवलंबन लेकर युवा सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है।

भारत की संस्कृति ने विश्व को यही सिखाया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता", इस ध्येय वाक्य को ध्यान में रखकर प्रदेश की योगी सरकार ने मिशन शक्ति, एवं सेफ सिटी योजना द्वारा महिला एवं बालिका सशक्तिकरण हेतु सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा प्रदेश की बालिकाओं एवं महिलाओं हेतु भाग्यलक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, विधवा पेंशन योजना, विवाह अनुदान योजना आदि के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर सफल प्रयास किए जा रहे हैं जो आधी आबादी के लिए सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु नवीन मानदंडों की स्थापना कर रहे हैं।

सुशासन की प्रक्रिया को सफल तभी माना जा सकता है जब हासिये पर पड़े हुए कतिपय वर्गों को भी उनका प्राप्तव्य मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांग पेशन योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना आदि के द्वारा अपवंचित एवं हासिये में पड़े हुए वर्गों को सुशासन के माध्यम से उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कराने तथा उनको स्वयं के प्राप्तव्य की ओर अग्रसारित करने के प्रयास कर रही है।

सुशासन की प्रक्रिया को सफल तभी माना जा सकता है जब हासिये पर पड़े हुए कतिपय वर्गों को भी उनका प्राप्तव्य मिले। उत्तर प्रदेश की सरकार दिव्यांग पेशन योजना, दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना तथा उत्तर प्रदेश आवास विकास योजना आदि के द्वारा अपवंचित एवं हासिये में पड़े हुए वर्गों को सुशासन के माध्यम से उनके अधिकारों की प्राप्ति सुनिश्चित कराने तथा उनको स्वयं के प्राप्तव्य की ओर अग्रसारित करने के प्रयास कर रही है।

समाज तभी सुशासन के पथ पर अग्रसर हो सकता है जब मनुष्य पुष्ट हों एवं उनका पेट भरा हो। भूख एवं भूख जनित कुपोषण से मुक्ति हेतु कृषि मुख्य अभिकरण है एवं कृषक इस अभिकरण का संचालन करने वाले कुशल अभिकर्ता हैं। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल करने के लिए योगी सरकार, उत्तर प्रदेश किसान उदय योजना, उत्तर प्रदेश निःशुल्क बोरिंग योजना, बीज ग्राम योजना, किसान ऋण मोचन योजना, मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, एवं पारदर्शी किसान सेवा योजना

के माध्यम से कृषि क्षेत्र की अवसंरचना को विकसित करने में आ रही समस्याओं को हल कर एवं किसान की आय दूनी करने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है एवं सुशासन की अवधारणा को कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में साकार कर रही है।

प्रदेश के सर्वांगीण विकास को गति देने हेतु औद्योगिक एवं श्रम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार नवीन राजमार्गों, नवीन हवाई पट्टियों आदि अवसंरचना को विकसित करते हुए औद्योगिक विकास को गति दे रही है। प्रदेश की श्रमशक्ति को औचित्यपूर्ण एवं सम्मानजनक आजिविका सुनिश्चित करने हेतु योगी सरकार ने पुराने उद्योगों को पुर्स्थापित करने के साथ ही नए उद्योंगों को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथ ही सरकार ने औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप श्रमिकों को प्रशिक्षित करने का काम किया है, जिससे प्रदेश की उन्नति के लिए बड़ी संख्या में कुशल श्रमशक्ति प्राप्त हो तथा प्रदेश की कार्य सक्षम युवा शक्ति को आसानी से रोजगार प्राप्त हो सके। इसके लिए शिक्षुता प्रोत्साहन योजना, कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना आदि के माध्यम से योगी सरकार ने प्रदेश की जनशक्ति का प्रदेश के लिए ही सार्थक उपयोग सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है एवं औद्योगिक एवं श्रम क्षेत्र को सुशासन की भावना से संचालित करने का प्रयास किया है।

किसी सरकार की सक्रियता, संबल, सहनशक्ति एवं संगठन की विशेषताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन आपत्तिकाल में होता है। प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कार्यकाल में कोविड–19 वैश्विक महामारी के भयावह काल में भी अपनी प्रशासनिक दक्षता का अत्युत्तम प्रदर्शन कर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश की जनता की निपक्ष भाव से सेवा की तथा प्रदेशवासियों को कोविड–19 के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने का भरसक प्रयत्न किया। प्रदेश की सरकार ने चिकित्सीय अवसंरचना के विकास हेतु नवीन मेडिकल महाविद्यालयों की स्थापना, कुशल चिकित्सकों की नियुक्ति, पर्याप्त संख्या में पैरामेडिकल कार्मिकों की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में औषधियों एवं चिकित्सीय उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की है। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में सुशासन को अभिकल्पित करने हेतु भगीरथ प्रयास कर प्रदेशवासियों के आरोग्य की रक्षा करने में अप्रतिम कार्य किया है।

सुशासन का एक अवयव समाज में शांति एवं समरसता भी है। शांति एवं समरसता ही वे तत्व हैं जो समाज की प्रगति हेतु उपजाऊ जमीन तैयार करते हैं। यदि रामराज्य का समानार्थी विश्लेषित किया जाए तो रामराज्य की प्रथम विशेषता शांति एवं समरसता के रूप में रेखांकि होगी, ये तभी संभव है जब कानून व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। आम नागरिकों में विधि के लिए सम्मान हो तथा अराजक तत्वों में विधि एवं व्यवस्था का भय हो। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधि व्यवस्था की स्थापना हेतु इष्टतम रूप से कार्य कर रही है। योगी सरकार "परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम" के मूल मंत्र से अनुप्राणित होकर शासन का संचालन कर सुशासन को स्थापित कर रही है।

सुशासन बहुमुखी, बहुविमीय, बहुध्रुवीय, सोद्देश्य एवं सतत संचालित होने वाली प्रक्रिया है। सुशासन केवल साध्य ही नहीं है अपितु साधन भी है अर्थात सुशासन के पथ पर अग्रसर होकर ही सुशासन के दैवीय लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। सुशासन की प्रक्रिया में न केवल राज्य, राज्य का संचालन करने वाली सरकार, राज्य की नीतियों को लागू करने वाला प्रशासन ही मुख्य भूमिका निभाते हैं अपितु जन भागीदारी की भी महती भूमिका है। जन सहभाग निर्वाचन के माध्यम से पूर्ण बहुमत वाली, सशक्त ईमानदार, राष्ट्र के प्रति निष्ठावान, संवैधानिक आदर्शों का अनुपालन करने वाली, सरकार के निर्वाचन के माध्यम से सुनिश्चित होता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने सुशासन के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु 2017 में भारतीय जनता पार्टी को शासन का उत्तरदायित्व सौंपा था। जब 2022 में पुनः सरकार के निर्वाचन हेतु जनसहभाग का अवसर आएगा तब प्रदेश की जनता निश्चय ही "सोच ईमानदार, काम दमदार" के ध्येय वाक्य को शिरोधार्य करके कार्य करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्वाचन कर सुशासन स्थापना के यज्ञ में अपने हिस्से की आहुति अवश्य डालेगी।

उत्तर प्रदेश को नंबर-1 बनाना ही हमारा संकल्प : योगी आदित्यनाथ

जन आकांक्षाओं सपनों का नम्बर एक उत्तर प्रदेश सबके सुझाव, सहयोग, प्रयास से बनेगा। इसके लिए भाजपा सबसे सुझाव माँगी है। इस पहल की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले आतंकियों के मुकदमे वापस होते थे, उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। आज यही माफिया मारे–मारे फिर रहे हैं। पहले नौकरी निकलते ही महाभारत काल दिखने लगता था। एक ही परिवार के चाचा–भतीजा, काका, मामा सभी वसूली के लिए निकल पड़ते थे। नियुक्तियों में जातिवाद–भाई भतीजा वाद होता था। वर्ष 2015 की सपा सरकार में डिप्टी कलेक्टर का रिजल्ट निकला तो 86 में से 56 लोगों के नाम एक ही विशेष जाति के आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि फर्क साफ है। प्रदेश वही है, संसाधन वहीं हैं केवल सरकार बदली है। कहा कि जनता के बहुमूल्य सुझावों की मदद से यूपी को नंबर–1 बनाना ही हमारा संकल्प है।

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी नंबर–1 अभियान में सुझाव आपका संकल्प हमारा कार्यक्रम में आकांक्षा पेटी लांच करते हुए कहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रदेश के गांव व शहरी क्षेत्रों के 30 हजार स्थानों पर आकांक्षा पेटी रखेगी। जनता से आने वाले सुझावों से संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा ने 2017 के चुनाव से पहले जो संकल्प पत्र जारी किया था, सरकार बनने पर सभी संकल्पों को हमने जीवन का व्रत मानकर पूरा किया। अब 2022 के लिए सुझाव आपका संकल्प हमारा के साथ हम फिर आए हैं। यह पहली सरकार है, जिसने 100 दिन, फिर छह महीने, एक वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष और फिर साढ़े चार वर्ष में अपना रिपोर्ट जारी किया।

सोच ईमानदार हो तो काम दमदार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार में एक करोड़ 71 लाख नौजवानों को रोजगार मिला है। प्रदेश में बड़े निवेश के कारण ढेर सारे रोजगार के रास्ते खुल चुके

जन सुझावों के आधार पर प्रदेश का विकास होगा

हैं। जहां विकास का कोई काम नहीं होता था वही प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे बना रहा है। मेडिकल कालेज बना रहा है। वाटर जलमार्ग तैयार कर रहा है। एयरपोर्ट बन रहे हैं। हमने पुलिस, शिक्षक सभी तरह की नियुक्ति की लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ। जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है।

वो गोली चलवाते थे, हमने किसानों की कर्जमाफी की,

उन्होंने कहा कि फर्क साफ है। पहले की सरकारें किसानों पर गोली चलाती थीं। हमने किसानों के लिए फसल ऋण माफी की घोषणा की थी। पहले आस्था के प्रतीकों का अपमान होता था। गोकशी होती थी, दंगे होते थे। हमारी सरकार आई तो अवैध स्लाटर हाउस बंद किए, गौ तस्करी रोकी। लगभग सात लाख गायों का संरक्षण किया। रिकार्ड मात्रा में क्रय केंद्रों की स्थापना और खरीद की। गन्ना किसानों के 10 वर्ष पुराने बकाए का भुगतान कराया। बंद चीनी मिलों को चालू कराया गया। पहले मां–बाप बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। 2017 के बाद प्रदेश की हर बेटी सुरक्षित है।

मोदी–योगी सरकार अंतिम व्यक्ति के उत्कर्ष को समर्पित: स्वतंत्रदेव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि भाजपा सपा और दूसरे दलों की तरह जातिवाद, वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं करती। प्रदेश की जनता ने 15 साल तक भ्रष्टाचार और गुंडाराज देखा है। भाजपा ने 2017 में जो संकल्प लिया था, सत्ता में आने के बाद उसे पूरा किया। विपक्ष को शिलान्यास और उद्घाटन से कष्ट नहीं है, उसे कष्ट समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की खुशहाली से है। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्कर्ष के लिए ही समर्पित हैं। उन्होंने लोगों से आकांक्षा पेटी में अधिकाधिक सुझाव डालने की अपील की। भाजपा संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष व वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनाकांक्षाओं को अपने संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने के लिए ही पार्टी ने आकांक्षा पेटी को प्रदेश में 30 हजार स्थानों पर रखवायी है।

साहिबजादों की शहादत..

श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा

माता गुजर कौर गुरु तेगबहादुर जी की पत्नी गुरुगोबिंद सिंह जी की माता चारो साहिबजादों की दादी शहीद भाई कृपाल चंद जी की बहन माता गुजर कौर जी ने पूरा जीवन शहीद परिवार के बीच बिताया युद्ध के लिए प्रेरित किया धर्म कौम के लिए अपना सब कुछ वार दिया सरहन्द के नवाब के फरमान पर दादी माँ ने अपने दोनों पोतों जोरावर सिंह 7 वर्ष और फतेह सिंह 5 वर्ष को तैयार करा सर पर कलगी सजा कर रवाना किया दादी माँ जानती थी उनके पोते अब वापस नही लौटेंगे एक बार दोनो पोतों को गले से लगाया माथा चूमा और विदा किया जब सरहन्द के नवाब के पास दोनो साहबजादे पहुचे तो फिर से जयकारा लगाया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सरहन्द के नवाब के आदेश पर नींव में चुनने एक खुले स्थान पर लाया गया और दोनो साहिबजादों के पैरों पर इट रुखकर दीवार चुनी जाने लगी जब दीवारों में चुना जाने लगा तो दीवार गुरू के लाडलों के घुटनों तक पहुंची तो घुटनों को नेजा से काट दिया गया ताकि दीवार टेढी न हो जाए शाशल बेग और वाशल बेग जल्लादों ने छोटे साहिबजादों को दीवारों में इटो से चिन दिया जब दीवार की ईंट छोटे फतेह सिंह तक पहुची तब बड़े बेटे जोरावर सिंह की आखो से आंसू बहने लगे फतेह सिंह ने पूछा वीर आंसू क्यो तब जोरावर सिंह कहते है कि पहले मैं इस दुनिया मे आया हुं लेकिन सहादत तुम्हे पहले नसीब हो रही है जल्लाद ने आखरी ईंट भी रख दी। देश कौम की रक्षा के लिए 7 और 5 वर्ष के दोनों लाल शहीद हो गए, छोटे साहिबजादों की शहीदी की खबर सुनकर दादी माता गुजरी जी ने भी देह त्याग दी। आज उस जगह पर बहुत ही सुन्दर गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप बना हुआ है जबकि शहादत वाली जगह पर बहुत बड़ा गुरूद्वारा है।

सूरासो पहचानिये जो लड़े दीन के–हेत।
पूर्जा पूर्जा कट मरे कबहून छोड़े–खेत ।।

दोनो छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह 7 वर्ष साहिबजादा फतेह सिंह 5 वर्ष और माता गुजर कौर जी की सहादत के बाद नवाब ने एलान कर दिया की कोई भी इनका अंतिम संस्कार न करे सरहंद में हर ओर मातम था मुगलिया आतंक नवाब के डर से लोग घरों में थे ऐसे में दिवान टोडरमल सामने आए इतिहास में दीवान टोडरमल का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। गुरु गोबिंदसिंह जी के छोटे साहिबजादों की सहादत के साथ साथ टोडरमल के साहस,उदारता और समर्पण भाव का सदैव जिक्र रहता है। टोडरमल सरहिंद का एक अमीर हिंदू जैन था। उसने अनूठी मिसाल पेश की साहिबजादों को जिंदा चिनवाने के बाद बेरहमी से शहीद करके माता गुजरीजी के पार्थिव शरीर सहित मौजूदा गुरुद्वारा श्रीफतहगढ़ साहिब के पीछे जंगल में रखा गया।वजीर खान के भय से छोटे साहिबजादों और माता गुजरी के अंतिम संस्कार के लिए कोई सामने नहीं आ रहा था। शाही फरमान जारी किया गया कि शवों का दाह संस्कार मुगलों की भूमि में नहीं किया जा सकता। संस्कार के लिए स्थान खरीदने की ऐसी शर्त रखी गई जिसे पूरा करना असंभव था। शर्त यह थी कि जितना स्थान चाहिए उतनी जगह पर स्वर्ण मोहरें बिछा कर खरीद कर लिया जाए। टोडरमल जब इसके लिए तैयार हुए तब नवाब ने शर्त रखी की सोने की मोहरे लिटाकर नही खड़ी करके बिछानी होगी सरहिंद के दीवान टोडरमल की सिख गुरुओं में बड़ी आस्था थी इतिहासकारों के मुताबिक टोडरमल ने 78000 स्वर्ण मुहरें बिछा कर विश्व का सबसे महंगा स्थान खरीदा 4 वर्ग मीटर की इस दुनिया की सबसे महंगी जमीन की कीमत उस वक्त के हिसाब से 2 अरब 50 करोड़ रुपयों की आकी गई टोडरमल ने दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदकर साहिबजादों व माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार किया।

सुशासन का संकल्प

लोकमंगल की राह पर सरकार

श्री अरूण कान्त त्रिपाठी

पिछले पांच वर्षों में लोक कल्याण संकल्प पत्र की सभी घोषणाओं को भाजपा की सरकार ने पूरा कर दिया है। सरकार द्वारा किये गये जनविकास कार्यों को अगर विपक्ष और चुनावी गणित समझाने वाले को पढ़ने एवं समझने की आदत होती तो अब तक ये सारे लोग कुछ सीख गए होते और जान गये होते कि विकास होता क्या है। किस तरह पिछले पांच वर्षों में प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की राह पर आगे बढाया है।

"उत्तर प्रदेश ने कारोबार में सुगमता में लंबी छलांग लगाई है और जो उत्तर प्रदेश 2016 में कारोबार में सुगमता में 14वें स्थान पर था वही प्रदेश आज दूसरे स्थान पर है।" 2016 में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था था लेकिन आज यह देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है। आस्था और धार्मिक स्थलों के विकास, राज्य में निवेश, कानून–व्यवस्था और सुरक्षा जैसे बिंदुओं पर अगर ध्यान दें तो आज हम पाते हैं कि केवल आंकड़ों में नहीं अपनी उपलब्धियों के साथ भाजपा सरकार सबसे आगे हैं। राज्य में सुरक्षा का बेहतर वातावरण बनने से बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। पारदर्शी कार्य पद्धति एवं त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश– दुनिया के बड़े–बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए उत्सुक है। जिस उत्तर प्रदेश को देश का विकास अवरुद्ध करने वाला राज्य कहा जाता था वही प्रदेश आज 44 परियोजनाओं में नंबर एक पर चल रहा है। फसलों की खरीद में पिछली सरकारों में आढ़तियों के जरिये उपज खरीदी जाती थी लेकिन भाजपा सरकार किसानों से सीधे उनकी उपज खरीद रही है।" इसे ही सुशासन कहा जाता हैं जहां पर सरकार जनता के द्वार तक जाती है। उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अक्षरशरू लागू करने के लिए अपनी योजना तैयार कर ली है।

इन 57 महीनों में में 42 लाख लोगों का 'अपने घर का सपना' पूरा हुआ है। 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 99 लाख लोगों के घर विद्युत कनेक्शन देकर घरों को रोशन किया गया है। 'उज्ज्वला' के तहत 1.6 करोड़ महिलाएं मुफ्त गैस कनेक्शन पाकर धुएं से उपजने वाली बीमारियों से बचीं। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को संबद्ध कर उनके आर्थिक उन्नयन का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी योजना के माध्यम से लगभग 59 हजार महिलाओं तक बैंकिंग व्यवस्था और प्रत्येक गांव तक बैंक पहुंचाया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आबादी लिए 5,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित कर रही है। सरकार का ये फैसला समुदायों को उनके घरों के करीब व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए सुविधाजनक बना है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और चिकित्सा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से काम किया है। इसके अलावा, सरकार ने राज्य में ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया। नतीजतन, राज्य के छोटे अस्पतालों से लेकर बड़े अस्पतालों में रेफर करने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आई है।

इन 5,000 नए स्वास्थ्य केंद्रों से स्वास्थ्य योजनाओं को भी सही तरीके से लागू किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग इन नए उपकेंद्रों पर आवश्यक चिकित्सा उपकरण, चिकित्सक व पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित कर रहा है। केंद्रों में मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, टीकाकरण,

किशोर स्वास्थ्य, मधुमेह, रक्तचाप की जांच और संचारी और गैर–संचारी रोगों के उपचार की व्यवस्था है। योग व व्यायाम, परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं जैसी गतिविधियां उपलब्ध है। टीकाकरण और मातृ स्वास्थ्य जांच और उपचार के अलावा मौसमी बीमारियों को फैलने से रोकने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक काम

- 59 जनपदों में न्यूनतम1मेडिकल कॉलेज क्रियाशील
- 16 जनपदों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज के स्थापना की प्रक्रिया
- गोरखपुर, रायबरेली एम्स का संचालन
- महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्विद्यालय गोरखपुर का निर्माण
- पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) में 6 करोड़ 47 लाख लोगों को बीमा कवर
- 42.19 लाख लोगों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवर
- लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण
- 6 नए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल ब्लॉक की स्थापना
- गोरखपुर, भदोही में वेटरनरी चिकित्सा विश्विद्यालय का निर्माण
- प्रदेश भर में 4470 एम्बुलेंस संचालित
- नियमित/संविदा पर 9512 चिकित्सकों एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती
- चिकित्सकों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई

उत्तर प्रदेश का भूगोल और प्रकृति उसे समृद्धि और विकास की बहुआयामी संभावनाओं से संपन्न बनाती है। इसके बावजूद इसकी गिनती बीमारू राज्य के रूप में होती रही। भाजपा सरकार ने किसान, श्रमिक, युवा और महिला सहित सभी वर्गों की सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण की दिशा में बढ़ना आरंभ किया, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास की व्यूहरचना बनाई। युवाओं को सरकार ने अन्य क्षेत्रों में नियोजन एवं रोजगार के अलावा पौने पांच लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान कीं।

बेसिक शिक्षा, शिक्षा की आधारभूत इकाई है। इसी को ध्यान में रखकर तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए निपुण (नेशनल इनीशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी) के तहत जीआईएस आधारित विद्यालयवार परफार्मेंस किट मैप, लर्निंग आउटकम मैप आधारित इस योजना का शुभारंभ हुआ है। निपुण भारत योजना, शिक्षा की मूलभूत इकाई पर कार्य करेगी। इससे बच्चों के विद्यालय छोड़ने की समस्या भी दूर होगी साथ ही नई शिक्षा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जा सकेगा। निपुण भारत योजना से प्रदेश के विद्यालयों को जोड़ने और विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन करने में मदद मिलेगी।

2017 में जब सरकार ने दायित्व संभाला था तो उस समय बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में एक करोड़ 30 लाख बच्चे पंजीकृत थे। पर, उस समय विद्यालयों की दशा बेहद दयनीय थी। पिछले साढ़े चार वर्ष में बेसिक शिक्षा परिषद ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और तकनीक अपनाकर पारदर्शी तरीके से न केवल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया, बल्कि छात्रों व शिक्षकों का अनुपात बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के भीतर उत्तर प्रदेश संभवतरू पहला ऐसा राज्य है जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद में छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लगभग 50 लाख बच्चे नये बढ़े हैं। विद्यालयों में क्लासरूम, फर्नीचर, टायलेट, शुद्ध पेयजल, स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हुई है।

किसान और कृषि को पहली कैबिनेट से वरीयता मिली। किसान को समय पर बीज और खाद, कम लागत और उपज को उपयुक्त कीमत मिले, इसकी व्यवस्था की गई। वर्ष 2020–21 में प्रदेश का कुल अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 618.49 लाख मीट्रिक टन रहा। सरकार ने एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीद की। गन्ना किसानों का अब तक 1.45 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

गांव और जनपदों को स्वावलंबी बनाने के लिए 'एक

जनपद–एक उत्पाद' कार्यक्रम को बढ़ाया गया। लाखों एमएसएमई इकाइयों को वित्तीय सुविधा प्रदान कर गति प्रदान की गई। इन्फ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ग्रोथ इंजन होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक्सप्रेसवे का संजाल विकसित करने के साथ–साथ जलमार्गों और वायुमार्गों को विकसित करने की दिशा में निर्णायक कार्य किया है। हाल ही में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को उद्घाटन और गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी कराकर प्रदेश सरकार ने एक नया इतिहास रचा है। बुन्देलखंड को घर–घर नल योजना से जोड़कर सरकार ने बुन्देलखंड की सैकडों वर्षों की प्यास का बुझाने का काम किया है।

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत

- पहली बार प्रदेश में हुए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट
- 8 एयरपोर्ट संचालित, 13 अन्य एयरपोर्ट एवं 7 हवाईपट्टी का विकास
- 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण हो रहा पूरा
- 297 किमी लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य प्रगति पर
- 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस–वे लिए हुआ भूमि अधिग्रहण, शिलान्यास जल्द
- 91 किमी लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस–वे का कार्य प्रगति पर
- बलिया लिंक एक्सप्रेस–वे को मिली मंजूरी

महिला सशक्तिकरण के लिये योगी सरकार द्वारा उठाए गए कदम अभूतपूर्व है। बालिकाओं को स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा भाजपा की सरकार ने दिया है। एक करोड़ 67 लाख मातृशक्तियों को उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस कनेक्शन दिये गये हैं। सीएम कन्या सुमंगला योजना से 9 लाख 36 हजार बेटियों को लाभ मिला है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 1.52 लाख से अधिक निर्धन कन्याओं का विवाह कराया गया है। पीएम मातृ वंदना योजना में 40 लाख माताएं लाभांवित हुई हैं। मुस्लिम महिलाओं को बिना महरम के हज पर जाने की सुविधा दी गई है। ग्रामीण आवासीय अभिलेख (घरौनी) वितरित, स्वामित्व अभिलेख (घरौनी) घर की महिला के नाम दिया जा रहा है। प्रदेश के सभी 1535 थानों में पहली बार महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। महिलाओं को तुरंत न्याय दिए जाने को लेकर 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय न्यायालय व 81 अपर सत्र की स्थापना हुई है। बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ योजना में 1 करोड़ 80 लाख बच्चियां लाभांवित हुई हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों की 18 हजार महिला मेटों का चयन किया गया है। करीब 56 हजार महिलाएं बैंकिंग सखी के रुप में कर रही हैं कार्य कर रही हैं। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एक करोड़ महिलाओं को रोजगार दिया गया है। 58,758 महिलाएं सामुदायिक शौचालयों में सफाई कर्मियों के रूप में चयनित हुई है। इसके सापेक्ष वर्ष 2007 से 2012 तक प्रदेश में 2,07,543 और वर्ष 2012 से 2017 में 83,148 नए स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ था. वर्ष 2007 से 2012 तक स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से 1,17,805 जबकि 2012 से 2017 तक 1,10,113 रोजगार दिए गए थे।

सकल आस्था के केंद्र प्रभु श्रीराम के भव्य–दिव्य मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास के साथ शताब्दियों से जारी साधना फलित हुई। श्रीकृष्ण की लीलास्थली ब्रज और मां विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का चिर प्रतीक्षित पुनरुद्धार भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित होकर पूरे विश्व में नई आभा बिखेर रहा है।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ईकाना स्टेडियम में अटल जी के जन्म दिन के अवसर पर प्रदेश के युवाओं को फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट देकर सरकार ने संकल्प पत्र का सारा वादा पूरा कर दिखाया है। सरकार प्रदेश के 70 लाख युवाओं को स्मार्टफोन और टेबलेट बांटने जा रही है। इसके अलावा सरकार ने डिजी शक्ति पोर्टल और डिजी शक्ति अध्ययन ऐप भी लांच कर दिया जिससे छात्रों को बहुत लाभ होगा। टेक्निकल छात्रों को टैबलेट और नॉन टेक्निकल को मोबाइल दिए जा रहे हैं।

प्रदेश वही है, लोग वही हैं, मेधा वही है। केवल दृष्टिकोण और कार्यसंस्कृति बदली है। अति साधारण व्यक्ति भी अब स्वयं को शासन का हिस्सा समझता है। विगत 57 महीनों में यही परिवर्तन, यही विश्वास हमने हासिल किया है।

उत्तर प्रदेश को 24 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सुरक्षित, समृद्ध, समुन्नत और आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए भाजपा सरकार अपने पाच वर्ष पूर्ण कर रही हैं। कोविड–19 जैसी वैश्विक महामारी में हमारे समक्ष जो चुनौतियां आईं, उनसे न केवल सफलतापूर्वक निपटा गया बल्कि 'लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय और पथ अंत्योदय' के लक्ष्य को साधते हुए आपदा को अवसर में भी बदला गया।

सरकार की उपलब्धियां

नवंबर, 2021 में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह, 1.31 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचा

नवम्बर, 2021 महीने में जीएसटी राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व की तुलना में 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है

केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा एक दिसंबर को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार नवम्बर, 2021 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 1,31,526 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी 23,978 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 31,127 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 66,815 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 32,165 करोड़ रुपये सहित) और उपकर (सेस) 9,606 करोड़ रुपये (वस्तुओं के आयात पर संग्रह किए गए 653 करोड़ रुपये सहित) शामिल हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नियमित निपटान के रूप में सीजीएसटी के लिए 27,273 करोड़ रुपये और आईजीएसटी से एसजीएसटी के लिए 22,655 करोड़ रुपये का निपटान किया। नवम्बर, 2021 में नियमित निपटान के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अणजत कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 51,251 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 53,782 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने 3 नवम्बर, 2021 को जीएसटी मुआवजे के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड़ रुपये भी जारी किए।

लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। नवम्बर, 2021 माह के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने के जीएसटी राजस्व से 25 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक रहा। इस महीने के दौरान वस्तुओं के आयात से प्राप्त राजस्व 43 प्रतिशत अधिक और घरेलू लेन-देन (सेवाओं के आयात सहित) से प्राप्त राजस्व पिछले साल के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक रहा।

नवम्बर, 2021 के लिए जीएसटी राजस्व जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक राजस्व रहा। यह अप्रैल, 2021 के बाद दूसरा बड़ा संग्रह है, जो साल के अंत के राजस्व से संबंधित था और पिछले

महीने के संग्रह से अधिक रहा, इसमें त्रैमासिक दाखिल की जाने वाली आवश्यक रिटर्न का प्रभाव भी शामिल रहा है। यह काफी सीमा तक आणथक सुधार की प्रवृत्ति के अनुरूप है।

अधिक जीएसटी राजस्व का यह वर्तमान रुझान विभिन्न नीतिगत और प्रशासनिक उपायों का परिणाम रहा है, जो अतीत में अनुपालन में सुधार करने के लिए उठाए गए हैं। केन्द्रीय कर प्रवर्तन एजेंसियों ने राज्य के समकक्षों के साथ जीएसटीएन द्वारा विकसित विभिन्न आईटी उपकरणों की मदद से बड़े कर चोरी के मामलों का पता लगाया है, जिनमें मुख्य रूप से नकली चालान से संबंधित मामले शामिल हैं, जो संदिग्ध करदाताओं का पता लगाने के लिए रिटर्न, चालान और ई-वे बिल डेटा का उपयोग करते हैं।

पिछले वर्ष बड़ी संख्या में पहल शुरू की गई हैं जिनमें सिस्टम क्षमता में बढ़ोतरी, रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि के बाद रिटर्न फाइल न करने वालों पर कार्रवाई, रिटर्न की ऑटो-पॉपुलेशन, ई-वे बिलों को अवरुद्ध करना और रिटर्न दाखिल न करने वालों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट पास करना आदि शामिल हैं। इससे पिछले कुछ महीनों के दौरान रिटर्न दाखिल करने में लगातार सुधार हुआ है। ■

भारत ने संस्थापित बिजली क्षमता में 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोत का लक्ष्य प्राप्त किया

गैर-जीवाश्म ऊर्जा आधारित कुल संस्थापित क्षमता 156.83 गीगावॉट

सीओपी-21 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में भारत ने 2030 तक अपनी संस्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई थी। देश ने नवंबर, 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दो दिसंबर को जारी एक बयान के अनुसार देश की संस्थापित अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता आज 150.05 गीगावॉट है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित संस्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावॉट है। इससे कुल गैर-जीवाश्म आधारित संस्थापित ऊर्जा क्षमता 156.83 गीगावॉट हो जाती है, यह 390.8 गीगावॉट की कुल संस्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है जो कि हाल ही में संपन्न सीओपी-26 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के अनुरूप है। सरकार वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट की संस्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

2021–22 की दूसरी तिमाही के जीडीपी में 8.4 प्रतिशत की हुई वृद्धि

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर को जारी एक प्रेस नोट के अनुसार 2021–22 की दूसरी तिमाही (जुलाई–सितंबर) में लगातार स्थिर मूल्यों (2011–12) पर जीडीपी 35.73 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में 32.97 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले दूसरी तिमाही में 7.4 प्रतिशत कमी की तुलना में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में मूल कीमतों पर तिमाही जीवीए 2021–22 में 32.89 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में 30.32 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 8.5 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

2021–22 की दूसरी तिमाही में स्थिर मूल्यों (2011–12) पर अनुमानित जीडीपी 55.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में यह 47.26 लाख करोड़ रुपये था, जिससे 17.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई थी। 2021–22 की दूसरी तिमाही के लिए बुनियादी मूल्य पर स्थिर (2011–12) मूल्यों पर तिमाही जीवीए अनुमानित रूप से 49.70 लाख करोड़ रुपये है जबकि 2020–21 की दूसरी तिमाही में 42.54 लाख करोड़ रुपये रहा था, इससे 16.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदर्शित होती है।

अप्रैल–सितंबर 2021–22 (एच1 2021–22) में स्थिर मूल्यों (2011–12) पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 59.92 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 68.11 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021–22 में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 15.9 प्रतिशत के संकुचन के मुकाबले 13.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। एच–1 2021–22 में मौजूदा कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 86.15 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 106.77 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो एच1 2021–22 में 23.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जबकि पिछले साल की इसी अवधि के दौरान 13.4 प्रतिशत के संकुचन को दर्शाता है।

भारत सरकार को अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,79,699 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार को अक्टूबर, 2021 तक कुल 12,79,699 करोड़ रुपये (कुल प्राप्तियों के संबंधित बजट अनुमान 2021–22 का 64.8 प्रतिशत) प्राप्त हुए, जिनमें 10,53,135 करोड़ रुपये का कर राजस्व (केंद्र के लिए विशुद्ध राशि); 2,06,842 करोड़ रुपये का गैर कर राजस्व और 19,722 करोड़ रुपये की गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं।

गैर–ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 10,358 करोड़ रुपये के ऋणों की वसूली और 9,364 करोड़ रुपये की मिलीजुली पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। अक्टूबर, 2021 तक भारत सरकार द्वारा करों में हिस्सेदारी के अंतरण के रूप में राज्य सरकारों को 3,07,687 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए हैं।

भारत सरकार द्वारा 18,26,725 करोड़ रुपये (संबंधित बजट अनुमान 2021–22 का 52.4 प्रतिशत) का कुल खर्च किया गया है, जिनमें से 15,73,455 करोड़ रुपये राजस्व खाते में हैं और 2,53,270 करोड़ रुपये पूंजीगत खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 3,99,737 करोड़ रुपये ब्याज भुगतान के मद में हैं और 2,09,916 करोड़ रुपये प्रमुख सब्सिडी के मद में हैं। ■

रत्न एवं आभूषण का निर्यात वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में दोगुने से भी अधिक हुआ

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 27 नवंबर को कहा कि भारत विश्व में सबसे बड़े हीरा व्यापारिक हब के रूप में उभर सकता है। उन्होंने कहा कि हमने खुद को हीरे की कटिंग तथा पॉलिशिंग के क्षेत्र में सबसे बड़ी हस्ती के रूप में स्थापित कर लिया है।

उल्लेखनीय है कि रत्न एवं आभूषण का निर्यात इस वित्त वर्ष के पहले सात महीनों— अक्टूबर, 2021 तक 23.62 बिलियन डॉलर तक रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 11.69 बिलियन डॉलर (+ 102.9 प्रतिशत) की तुलना में दोगुने से भी अधिक रहा। श्री गोयल ने कहा कि हमारे विनिर्माताओं की उत्कृष्ट गुणवत्ता ने हमें दुबई-यूएई, अमेरिका, रूस, सिंगापुर, हांगकांग तथा लातिनी अमेरिका जैसे बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाया है। ■

ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों ने कराया पंजीकरण

करीब 48 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक पुरुष हैं और शेष 52 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। लगभग 61 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक 18–40 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जबकि लगभग 22 प्रतिशत 40–50 वर्ष आयु वर्ग के हैं

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार श्रमिकों के पंजीकरण में तेजी लाते हुए ई–श्रम पोर्टल (असंगठित श्रमिकों) का राष्ट्रीय डेटाबेस) ने एक दिसंबर को 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। यह 26 अगस्त, 2021 को शुरू हुआ था।

इस उपलब्धि को 'संकल्प से सिद्धि' की यात्रा बताते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि देश के करोड़ों श्रमिकों और कामगारों का सामर्थ्य आज नए भारत का आधारस्तंभ बन रहा है। उनकी सामाजिक सुरक्षा में ही देश का मजबूत भविष्य छिपा है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने निर्माण श्रमिकों, प्रवासी श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, सड़क विक्रेताओं, घरेलू श्रमिकों, कृषि श्रमिकों सहित अन्य असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ईएसएचआरएएम (ई–श्रम) पोर्टल (ूमीतंउ.हवअ.पद) 26 अगस्त, 2021 को शुरू किया गया था।

आधार से जुड़े ई–श्रम पोर्टल का उपयोग असंगठित श्रमिकों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ई–श्रम पोर्टल पर सभी पात्र पंजीकृत श्रमिकों को पॉलिसी जारी होने की तारीख से पीएमएसबीवाई के तहत 2 लाख का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है।

भारत सरकार ने असंगठित कामगारों के पास जाकर पंजीकरण की सुविधा प्रदान की है। कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) देशभर में अपने 4 लाख से ज्यादा केंद्रों के माध्यम से पंजीकरण एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। पंजीकरण सुविधा का विस्तार करने के लिए राज्य सरकारें भी 17,337 से ज्यादा राज्य सेवा केंद्रों को ई–श्रम पोर्टल के साथ जोड़ चुकी हैं। कामगार खुद ई–श्रम पोर्टल पर जाकर भी पंजीकरण कर सकते हैं। फिलहाल, 81प्रतिशत पंजीकरण सीएससी और एसएसके द्वारा किया जा रहा है और शेष 19प्रतिशत स्वयं पंजीकरण किया जा रहा है।

करीब 48 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक पुरुष हैं और शेष 52 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं हैं। ट्रांसजेंडरों को भी ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा रहा है। ई–श्रम पर अब तक 2,380 ट्रांसजेंडर पंजीकृत किए जा चुके हैं। लगभग 61 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिक 18–40 वर्ष आयु वर्ग के हैं जबकि लगभग 22 प्रतिशत 40–50 वर्ष आयु वर्ग के हैं।

ई–श्रम पोर्टल के तहत श्रमिकों को उनके व्यवसाय से पहचान दिलाने के लिए व्यवसाय भी दर्ज किया जा रहा है। यह सरकारों को असंगठित कामगारों के सभी वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा वाली कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में सुविधा प्रदान करेगा। 30 व्यापक क्षेत्र की श्रेणियों वाली गतिविधियां, 190 बड़े व्यवसायों के क्षेत्र और करीब 400 व्यवसाय हैं। यह व्यवसायों का राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण, 2015 पर आधारित है। ■

देश की 50 प्रतिशत टीका-योग्य आबादी का पूर्ण टीकाकरण हुआ

देश की 50 प्रतिशत टीका-योग्य आबादी पूरी तरह से टीकाकृत हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर कहा कि बधाई हो भारत। यह बहुत गर्व का क्षण है, क्योंकि 50 प्रतिशत से अधिक योग्य आबादी को अब पूरी तरह से टीकाकृत किया गया है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लेने पर हर्ष व्यक्त किया। श्री मंडाविया के ट्वीट के उत्तर में प्रधानमंत्री ने छह दिसंबर को कहा कि भारत के टीकाकरण अभियान ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बनाने के लिये इस निरंतरता को बनाये रखना जरूरी है। साथ ही, श्री मोदी ने यह भी कहा कि मास्क लगाने और सामाजिक दूरी का ध्यान रखने सहित कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का बराबर पालन किया जाता रहे। ■

भारत में कोविड-19 टीकाकरण का कुल कवरेज 127.93 करोड़ के पार

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार छह दिसंबर की सुबह सात बजे तक (अनन्तिम रिपोर्ट) देश का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज 127.93 करोड़ (1,27,93,09,669) के पार पहुंच गया। इसे 1,30,65,773 सत्रों के जरिये पूरा किया गया।

भारत की रिकवरी दर इस समय 98.35 प्रतिशत है। सक्रिय मामले इस समय देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.28 प्रतिशत है, जो मार्च, 2020 से अपने न्यूनतम स्तर पर है। समग्र रूप से भारत में अब तक 64.82 करोड़ से अधिक (64,82,59,067) जांचें की गईं हैं। ■

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप

अटल बिहारी वाजपेयी

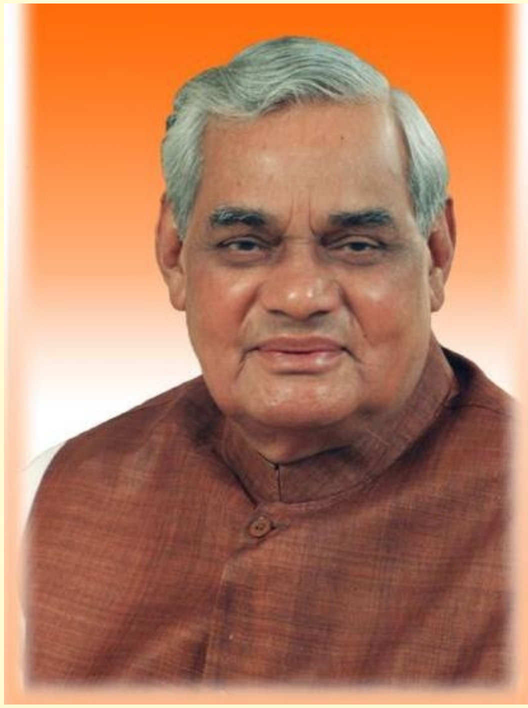

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की स्पष्ट कल्पना लेकर चलें। राष्ट्र कुछ संप्रदायों अथवा जनसमूहों का समुच्चय मात्र नहीं, अपितु एक जीवमान इकाई है, जिसे जोड़–तोड़कर नहीं बनाया जा सकता। इसका अपना व्यक्तित्व होता है, जो उसकी प्रकृति के आधार पर कालक्रम का परिणाम है। उसके घटकों में राष्ट्रीयता की यह अनुभूति, मातृभूमि के प्रति भक्ति, उसके जन के प्रति आत्मीयता और उसकी संस्कृति के प्रति गौरव के भाव में प्रकट होती है। इसी आधार पर अपने–पराये का, शत्रु–मित्र, अच्छे–बुरे और योग्य–अयोग्य का निर्णय होता है। जीवन की इन निष्ठाओं तथा मूल्यों के चारों ओर विकसित इतिहास, राष्ट्रीयत्व की भावना घनीभूत करता हुआ, उसे बल प्रदान करता है। उसी से व्यक्ति को त्याग और समर्पण की, पराक्रम और पुरुषार्थ की, सेवा और बलिदान की प्रेरणा मिलती है।

भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। स्वतंत्रता की प्राप्ति से, इसके चिरकालीन इतिहास में एक नये अध्याय का प्रारंभ हुआ। किसी नवीन राष्ट्र का जन्म नहीं। भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है। राजनीतिक एकता के अभाव ने देश की सांस्कृतिक धारा को कभी खण्डित नहीं होने दिया। जहां एक ओर हम भारत की संस्कृति से अभिन्न रूप से संबद्ध अनेक राजनीतिक इकाइयों के प्रति उदासीन तथा सहिष्णु रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय संस्कृति से भिन्न उसके विकृत अथवा विरोधी भाव पर आधारित, कोई भी राजनीतिक सत्ता हमें मान्य नहीं हुई। हम सदैव उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं।

भारतीय राष्ट्र का मूल स्वरूप राजनीतिक नहीं सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता की अनुभूति ही राजनीतिक एकता के पक्ष की प्रेरक शक्ति रही है।

विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है। हमने एकरूपता की नहीं, अपितु एकता की कामना की है। फलतः देश में अनेक उपासना पद्धतियों, पंथों, दर्शनों, जीवन–प्रणालियों, भाषाओं, साहित्यों और कलाओं का विकास हुआ, जो सम्पन्नता की द्योतक हैं। हमें उनके प्रति अपनत्व और गौरव का भाव लेकर चलना होगा। किन्तु, विविधता के नाम पर विभाजन को प्रोत्साहन देना भूल होगी। भारतीय संस्कृति कभी किसी एक उपासना पद्धति से बंधी नहीं रही और न उसका आधार प्रादेशिक ही रहा है। मजहब अथवा क्षेत्र के आधार पर पृथक् संस्कृति की चर्चा तर्क–विरुद्ध ही नहीं, भयावह भी है, क्योंकि वह राष्ट्रीय एकता की जड़ पर ही कुठाराघात करती है।

क्षेत्र, प्रदेश, जाति, पंथ, भाषा, भूषा आदि के आधार पर भारतीय जन की पृथकता की कल्पना भ्रामक है। उनके आधार पर भारत में अनेक राष्ट्रों अथवा राष्ट्रीयताओं के अस्तित्व का विचार भी मूलतः अशुद्ध है। हम एक राज्य में रहने के कारण एक नहीं हैं, अपितु हम एक हैं, इसलिए भारत एक राष्ट्र है।

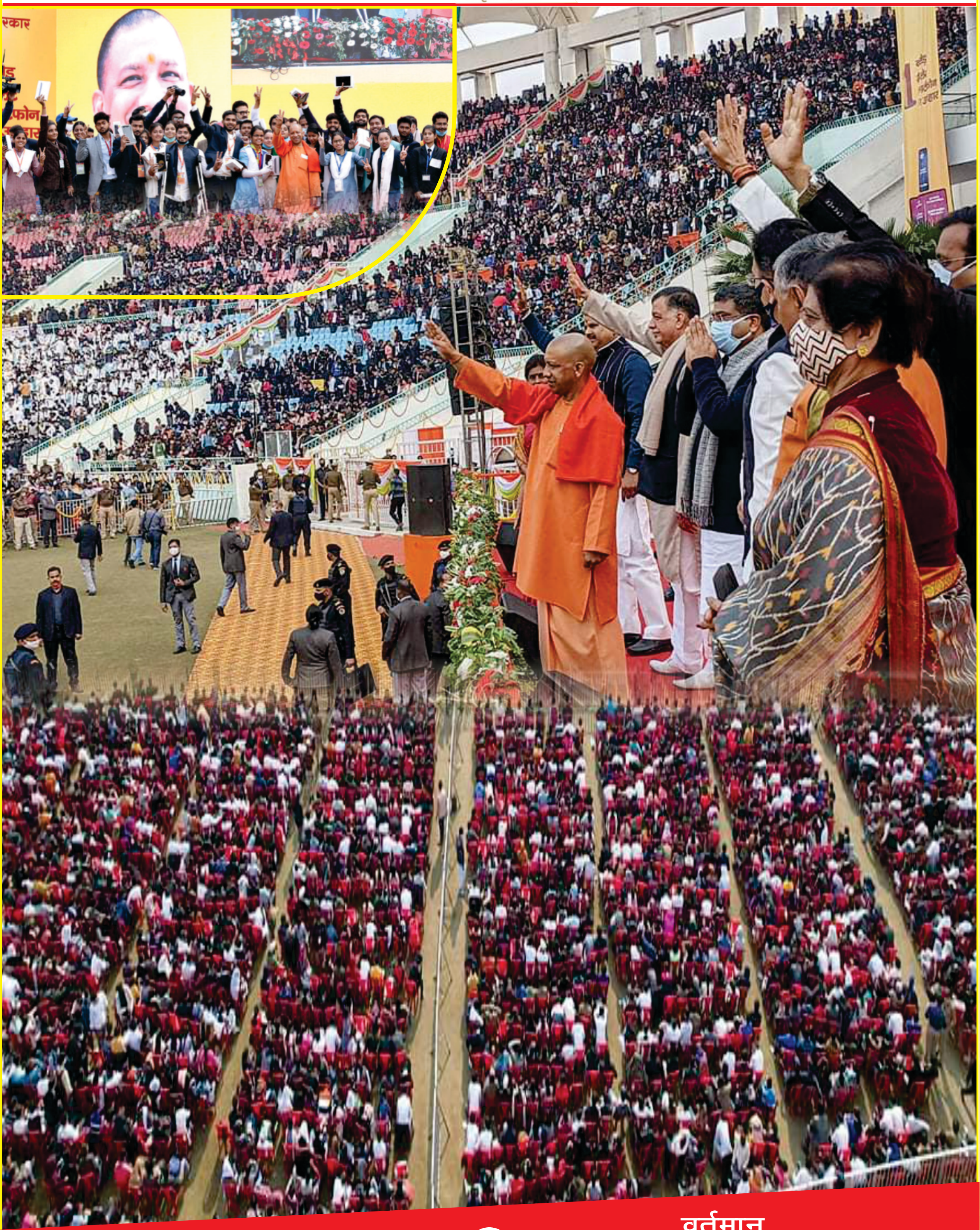

पत्रिका पंजीकरण – RNI-51899/91 डाक पंजीकरण – SSP/LW/NP-117-2021-23
दिसम्बर द्वितीय 2021 – प्रेषित डाकघर – R.M.S. चारबाग, लखनऊ – प्रेषण तिथि : 26–29 (द्वितीय पाक्षिक)

भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्रक तथा प्रकाशक प्रो. श्यामनन्दन सिंह द्वारा नूतन ऑफसेट मुद्रण केन्द्र, संस्कृति भवन, राजेन्द्र नगर, लखनऊ से मुद्रित व भाजपा कार्यालय, 7, विधानसभा मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक : अरूण कान्त त्रिपाठी